

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(आयकर)

अधिसूचना - 22

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई, 2018

सा.का.\_\_\_\_\_(अ) - जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा कतर राज्य की सरकार के बीच करार (इसे इसके बाद "डीटीए" कहा जाएगा) पर 07 अप्रैल, 1999 को हस्ताक्षर किए गए थे।

जबकि, डीटीए के अनुच्छेद 11 के पैरा 3 के खंड (ii) में सरकारी वित्तीय संस्थानों/एजेंसियों द्वारा प्राप्त और लाभप्रद रूप से स्वामित्व वाले ब्याज पर छूट देने के लिए पारस्परिक करार का प्रावधान है;

और जबकि, अनुच्छेद 11 के पैरा 3 के खंड (ii) के अनुसार भारत गणराज्य के 16 मार्च, 2018 के, और कतर राज्य द्वारा उनके दिनांक 29 अप्रैल, 2018 के पत्र के द्वारा यथा स्वीकृत, पत्र के आदान-प्रदान के माध्यम से 29 अप्रैल, 2018 को एक पारस्परिक करार पर सहमति हुई है और भारत-कतर डीटीए के अनुच्छेद 11 के पैरा 3 के खंड (ii) के अनुसार ब्याज सम्बंधी आय पर कर से छूट देने के लिए भारत गणराज्य और कतर राज्य के बीच कथित पत्रों (इसके साथ यथा संलग्न) का आदान-प्रदान किया गया था;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से कथित पारस्परिक करार के उपबंध भारत संघ में 29 अप्रैल, 2018 से लागू किए जाएंगे।

अनुबंध

दिनांक 16 मार्च, 2018 के भारत गणराज्य की सरकार द्वारा हस्ताक्षरित पत्र

प्रिय श्री घानिम खलीफा अल आलिया

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से मैं भारत गणराज्य की सरकार तथा कतर राज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार (डीटीए) का संदर्भ लेता हूँ जो 15 जनवरी, 2000 को प्रभावी हुआ।

कतर राज्य की सरकार की ओर से प्रस्ताव तथा भारत गणराज्य की सरकार की ओर से प्रस्ताव पर उक्त डीटीए के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 की खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए विचार करते हुए निम्नलिखित सरकारी वित्तीय संस्थान/एजेंसियां इस परस्पर करार के होने की तिथि से उक्त अनुच्छेद 11(3)(ii) के अंतर्गत ब्याज आय पर कर छूट प्रदान करने के लिए दोनों संविदाकारी राज्य के बीच परस्पर रूप से सहमत हुई हैं:

(क) भारत के मामले में भारतीय आयात-निर्यात बैंक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम; और

(ख) कतर के मामले में कतर निवेश प्राधिकरण तथा कतर होल्डिंग एलएलसी

यदि पूर्ववर्ती प्रस्ताव कतर राज्य की सरकार को स्वीकार है, तो मैं भारत गणराज्य की सरकार की ओर से सुझाव देता हूँ कि वर्तमान टिप्पण उस दिन से दोनों सरकारों के बीच उक्त भारत-कतर डीटीए के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 के खण्ड (ii) के बारे में किए गए परस्पर करार के गठन के रूप में माना जाए, जिस दिन से आप औपचारिक रूप से इसकी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं।

सादर,

भवदीय,

ह0/-

(सुशील चंद्र)

कतर राज्य की सरकार द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 2018 को हस्ताक्षरित पत्र

प्रिय श्री सुशील चंद्र

कतर राज्य सरकार की ओर से मुझे आपके दिनांक 16 मार्च, 2018 का नोट प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो निम्नानुसार पठित है:

"भारत गणराज्य की सरकार की ओर से मैं भारत गणराज्य की सरकार तथा कतर राज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार (डीटीए) का संदर्भ लेता हूँ जो 15 जनवरी, 2000 को प्रभावी हुआ।

कतर राज्य की सरकार की ओर से प्रस्ताव तथा भारत गणराज्य की सरकार की ओर से प्रस्ताव पर उक्त डीटीए के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 की खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए विचार करते हुए निम्नलिखित सरकारी वित्तीय संस्थान/एजेंसियां इस परस्पर करार के होने की तिथि से उक्त अनुच्छेद 11(3)(ii) के अंतर्गत ब्याज आय पर कर छूट प्रदान करने के लिए दोनों संविदाकारी राज्य के बीच परस्पर रूप से सहमत हुई हैं:

(क) भारत के मामले में भारतीय आयात-निर्यात बैंक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम; और

(ख) कतर के मामले में कतर निवेश प्राधिकरण तथा कतर होल्डिंग एलएलसी

यदि पूर्ववर्ती प्रस्ताव कतर राज्य की सरकार को स्वीकार है, तो मैं भारत गणराज्य की सरकार की ओर से सुझाव देता हूँ कि वर्तमान टिप्पण उस दिन से दोनों सरकारों के बीच उक्त भारत-कतर डीटीए के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 के खण्ड (ii) के बारे में किए गए परस्पर करार के गठन के रूप में माना जाए, जिस दिन से आप औपचारिक रूप से इसकी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं।"

उत्तर में, कतर राज्य की सरकार की ओर से मुझे यह कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कतर राज्य की सरकार इसमें किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करती है तथा इस उत्तर को दोनों सरकारों के बीच भारत-कतर डीटीए के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 के खण्ड (ii) की शर्तों के अनुसार आज से एक पारस्परिक समझौता माना जाए।

सादर,

भवदीय,

ह0/-

बानिम खलीफा अल आतिया

[अधिसूचना सं. 32 /2018/ 504/6/2004-एफटीडी-II (खंड1)]

रजत बंसल  
(रजत बंसल)

12.7.18

संयुक्त सचिव भारत सरकार

PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)  
(INCOME TAX)

32 NOTIFICATION

New Delhi, the 17<sup>th</sup> July, 2018

S.O.\_\_\_\_(E).- Whereas, the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Qatar for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (hereinafter referred to as the "DTAA") was signed on the 7<sup>th</sup> April, 1999;

Whereas, clause (ii) of para 3 of Article 11 of DTTA provides for the mutual agreement for granting exemption from tax on interest derived and beneficially owned by governmental financial institutions/agencies;

And whereas, in accordance with clause (ii) of para 3 of Article 11 a mutual agreement has been reached on the 29<sup>th</sup> April 2018, through exchange of letter dated the 16<sup>th</sup> March, 2018 of Republic of India and duly accepted by State of Qatar vide their letter dated the 29<sup>th</sup> April, 2018 and the said letters were exchanged between the Republic of India and the State of Qatar (as annexed herewith) for grant of exemption from tax on interest income, in accordance with clause (ii) of paragraph 3 of Article 11 of the India-Qatar DTAA;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that the provisions of said Mutual Agreement through exchange of letters, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India with effect from 29<sup>th</sup> April, 2018.

Annexure

Letter signed by the Government of the Republic of India on 16<sup>th</sup> March, 2018

Dear Mr. Ghanim Khalifa Al Attiyah

On behalf of the Government of the Republic of India, I have the honour to refer to the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Qatar for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (DTAA) which came into force on 15<sup>th</sup> January, 2000.

Considering the proposal on behalf of the Government of the State of Qatar and the proposal on behalf of the Government of the Republic of India, for the purposes of clause (ii) of paragraph 3 of Article 11 of the said DTAA, following governmental financial institutions/agencies are mutually agreed upon between the two Contracting States for granting tax exemption on interest income under the said Article 11(3)(ii) from the date of reaching this mutual agreement:

- (a) In the case of India, the Export Import Bank of India and Life Insurance Corporation of India; and
- (b) In the case of Qatar, the Qatar Investment Authority and Qatar Holding LLC.

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the State of Qatar, on behalf of the Government of the Republic of India, I have the honour to suggest that the present note be regarded as constituting a mutual agreement reached in terms of clause (ii) of paragraph 3 of Article 11 of the said India-Qatar DTAA between the two Governments, on the day you formally confirm its acceptance.

Regards

Yours sincerely,  
Sd/-

(Sushil Chandra)

Letter signed by the Government of the State of Qatar on 29<sup>th</sup> April, 2018

Dear Mr. Sushil Chandra

On behalf of the Government of the State of Qatar, I have the honour to acknowledge receipt of your note dated 16<sup>th</sup> march, 2018, which reads as follows:

" On behalf of the Government of the Republic of India, I have the honour to refer to the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Qatar for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (DTAA) which came into force on 15<sup>th</sup> January, 2000.

Considering the proposal on behalf of the Government of the State of Qatar and the proposal on behalf of the Government of the Republic of India, for the purposes of clause (ii) of paragraph 3 of Article 11 of the said DTAA, following governmental financial institutions/agencies are mutually agreed upon between the two Contracting States for granting tax exemption on interest income under the said Article 11(3)(ii) from the date of reaching this mutual agreement:

- (a) In the case of India, the Export Import Bank of India and Life Insurance Corporation of India; and

(b) In the case of Qatar, the Qatar Investment Authority and Qatar Holding LLC.

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the State of Qatar, on behalf of the Government of the Republic of India, I have the honour to suggest that the present note be regarded as constituting a mutual agreement reached in terms of clause (ii) of paragraph 3 of Article 11 of the said India-Qatar DTAA between the two Governments, on the day you formally confirm its acceptance."

In reply, on behalf of the Government of the State of Qatar, I have the honour to say that the Government of the State of Qatar accepts the proposal made therein and this reply shall constitute a mutual agreement reached today in terms of clause (ii) of paragraph 3 of Article 11 of the India-Qatar DTAA, between the two Governments.


Regards,

Yours sincerely,

Sd/-

Ghanim Khalifa Al Attiyah

[Notification No. 32/2018/ 504/6/2004-FTD-II(Pt.1)]

  
(RAJAT BANSAL) 12.7.2018

Joint Secretary to the Government of India